सूचना का अधिकार अधिनियम/नियमों के तहत प्रकटीकरण के तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा की सारांश रिपोर्ट

मंत्रालय का नाम: जनजातीय कार्य मंत्रालय

सार्वजनिक प्राधिकरण का नाम: नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

यह बहुत सारी उपयोगी जानकारी के साथ **हेल्प जोन** और **ई-नागरिक** के प्रावधान युक्त एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई वेबसाइट है । विशेष रुप से सहायता विंडो पर सूचना प्रसार प्रणाली का प्रावधान भी प्रशंसनीय है । फिर भी, आगे सुधार की गुंजाइश है । नीचे उल्लिखित कुछ बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है ।

1. इसे और अधिक नागरिक अनुकूल बनाने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को उचित लिंक प्रदान करना होगा ।
2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में वर्णित नियम पुस्तिका आरटीआई पोर्टल में अलग से प्रकाशित किया जाना चाहिए, जहां उन साइटों के लिंकों के संकेत सहित आगे जानकारी प्रदान की जाती है ।
3. खरीद समिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि नवीनतम खरीद,विवेकाधीन/गैर-विवेकाधीन अनुदान, अनुबंध, संसदीय प्रश्न और उत्तर,आरटीआई आवेदनों की प्रति/अपील और इसके जवाब आवेदकों के विवरण का खुलासा किए बिना खुलासा नहीं किया गया है । ऐसी जानकारी का नागरिक अनुकूल तरीकों से प्रासंगिक अधिनियम/ नियम/ निर्देश प्रावधान के अनुसार खुलासा करने की आवश्यकता है ।
4. आरटीआई की समझ को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल तरीके से कर्मचारियों को प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है ।
5. आरटीआई पर सूचना मैनुअल/हैंडबुक स्थानीय भाषाओं में तैयार की जा सकती है और वेबसाइट पर अपलोड की जा सकती है । मुद्रित सामग्री नागरिकों के लिए सुविधाजनक आउटलेट पर उपलब्ध कराई जा सकती है ।
6. इसकी वैधता के साथ एसटीक्यूसी प्रमाणपत्र का विवरण वेबसाइट पर दिखाया जाना चाहिए ।